दैनिक जागरण

सत्संग मानसिक समस्याओं का उपचार है

राहत देने की कोशिश

आम चुनाव का सामना करने जा रही सरकार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह अंतरिम बजट में चुनाव की चिंता न करे। इस पर हैरानी नहीं कि कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की ओर से पेश अंतरिम बजट के जरिये मोदी सरकार ने समाज के सभी तबकों और खासकर किसानों एवं मजदूरों के साथ वेतनभोगी मध्य वर्ग को खास तौर पर राहत देने की कोशिश की है। जहां दो हेक्टेयर तक खेती की जमीन वाले किसानों को छह हजार रुपये सालाना देने की घोषणा की गई है वहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन देने की भी एक योजना पेश की गई है। इसके अतिरिक्त पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को आयकर न देने की व्यवस्था भी की गई है। ये तीनों उल्लेखनीय कदम संबंधित तबकों को राहत देने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे देश का मूड और माहौल बदलेगा? यह सवाल इसलिए, क्योंकि किसानों और मजदूरों के संदर्भ में जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं उनके अमल के बाद ही यह पता चलेगा कि मुश्किल हालात से दो-चार हो रहे ये दोनों तबके कितने संतुष्ट हुए? चूंकि किसानों को न्यूनतम आमदनी वाली योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी इसलिए आम चुनाव तक उन्हें पहली किश्त मिल सकती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हाल-फिलहाल कोई लाभ मिलने की सूरत नहीं दिख रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की पेंशन योजना के साथ ही छोटे एवं सीमांत किसानों के खाते में सीधे धन पहुंचाने की योजना पर अमल आसान काम नहीं, क्योंकि इसका आकलन करने में कठिनाई हो सकती है कि किस किसान के नाम वास्तव में कितनी जमीन है या फिर किस मजदूर की आय 15 हजार रुपये महीने से कम है?

यह सही है कि सरकार सीधे धन हस्तांतरण की तकनीक से लैस है और कई कल्याणकारी योजनाओं में उसका सफल प्रदर्शन भी हो चुका है, लेकिन इसका अंदेशा है कि अंतरिम बजट में घोषित कल्याणकारी योजनाओं के जरिये उपलब्ध कराई जाने वाली मदद अपेक्षाओं के अनुरूप न साबित हो। पता नहीं किसानों और मजदूरों को राहत देने वाली योजनाओं में देरी के कोई दुष्परिणाम सामने आएंगे या नहीं, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि इन तबकों को प्राथमिकता के आधार पर राहत देने की दरकार थी। एक तरह से यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह इन वर्गों और साथ ही मध्य वर्ग की सुध ले। स्पष्ट है कि ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं कि चुनाव सामने देखकर सरकार ने लोक-लुभावन योजनाओं की झड़ी लगा दी। ऐसा इसलिए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खजाने का मुंह खोलने के बावजूद सरकार ने राजकोषीय घाटे की चिंता की है। शायद यही कारण है कि वैसी कोई घोषणा नहीं की गई जिसके लिए दबाव बनाया जा रहा था और इस क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि उन्होंने तो हर गरीब के खाते में पैसा पहुंचाने का फैसला कर लिया है। कोई भी सरकार हो उसे चुनाव की चिंता के साथ देश की आर्थिक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए।

कर्मचारी आंदोलन

उत्तराखंड में एक बार फिर कर्मचारी संगठनों का आंदोलन पर जाना चिंताजनक है। जिस तरह से कर्मचारी संगठनों ने इस आंदोलन में एकता दिखाई है, उसमें कहीं न कहीं उनके भीतर के भारी असंतोष की झलक दिख रही है। यह स्थिति उचित नहीं कही जा सकती। वैसे तो उत्तराखंड राज्य का गठन ही आंदोलन की नींव पर हुआ। इसलिए आंदोलन यहां के लिए नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीते वर्षों में कर्मचारी आंदोलनों की संख्या बढ़ी है, उससे उत्तराखंड की छवि हड़ताली प्रदेश के रूप में बन रही है, जो प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। वैसे तो अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना कर्मचारियों का हक है, लेकिन साथ ही उन्हें कर्मचारी आचरण नियमावली और आम जनता की परेशानी का भी संज्ञान रखना चाहिए। कर्मचारियों को यह समझना होगा कि आंदोलन या हड़ताल दबाव बनाने का काम तो कर सकती है, लेकिन हल वार्ता से ही निकलता है। ऐसे ही सरकार को भी चाहिए कि वह कर्मचारियों से उनकी मांगों को लेकर निरंतर संवाद करे। ग्रीवांस कमेटी बनाने अथवा कर्मचारी संगठनों से वार्ता करने का कदम अंतिम दौर में उठाना उचित नहीं ठहराया जा सकता। जब कर्मचारियों को वार्ता पर आमंत्रित करना ही था तो क्यों सामूहिक अवकाश के कार्यक्रम के दिन ही इसका चयन किया गया। कर्मचारी संगठन तो एक पखवाड़े पहले आंदोलन का कार्यक्रम सरकार को सौंप चुके थे तो क्यों नहीं शुरू में ही उनसे संवाद स्थापित किया गया। यदि पहले ही कर्मचारियों से वार्ता हो गई होती तो आंदोलन की नौबत शायद न आती। साफ है कि संवादहीनता ही कर्मचारियों एवं सरकार के बीच टकराव का कारण बनी। मौजूदा समय में कर्मचारी आंदोलन अथवा हड़ताल प्रदेश के हित में बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस समय उत्तराखंड को एक बड़े निवेश करने योग्य प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। बीते वर्ष आयोजित निवेशक सम्मेलन में भी उत्तराखंड में कई बड़ी कंपनियों एवं उद्योगपतियों ने निवेश में रुचि दिखाई। इस तरह के आंदोलन निवेशकों को चिंतित करते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह ऐसी नौबत न आने दे।

संतुलन साधने की कामयाब कवायद

धर्मकीर्ति जोशी

मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के जरिये अपेक्षाओं के दबाव को खजाने की सेहत को ज्यादा बिगाड़े बिना ही पूरा करने की कोशिश की है

अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाओं पर गौर करें तो इसमें कुछ भी अनपेक्षित नहीं है। जल्द ही होने जा रहे आम चुनाव और देश के मौजूदा हालात की छाप इस बजट पर नजर आती है। चुनावी साल में सरकार पर लोकलुभावन बजट पेश करने का भारी दबाव होता है और उसे अपने संसाधनों के लिहाज से संतुलन भी साधना होता है तो ऐसी स्थिति में बजट पेश करना स्वाभाविक रूप से एक बड़ी चुनौती होती है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल काफी हद तक इस चुनौती का तोड़ निकालने में सफल हुए हैं। उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया जो राजकोषीय संतुलन के साथ ही काफी हद तक लोकलुभावन स्वरूप वाला भी है जिसमें समाज के प्रत्येक तबके के लिए कुछ न कुछ गुंजाइश रखी गई है। एक बड़ी हद तक इसे समावेशी बजट कह सकते हैं। यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अपेक्षाओं के दबाव को सरकार ने अपने खजाने की सेहत को ज्यादा बिगाड़े बिना ही पूरा करने की कोशिश की है।

देश में किसानों का संकट किसी से छिपा नहीं। पिछले कुछ अर्से में किसानों के तमाम आंदोलनों को देखते हुए व्यापक रूप से माना जा रहा था कि सरकार उन्हें कुछ न कुछ सौगात देगी। ऐसा ही हुआ। किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना की निश्चित आमदनी वाली योजना इस दिशा में एक बड़ी पहल है। इसी तरह पांच लाख रुपये तक की आमदनी को आयकर से मुक्त करना भी मध्य वर्ग को एक बड़ी राहत है।

अंतरिम बजट का मर्म यही है कि सरकार का पूरा ध्यान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उपभोग को बढ़ाने पर है। इस कवायद के लिए निश्चित रूप से जहां अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी वहीं कुछ राजस्व नुकसान की आशंका भी बढ़ेगी। सरकार के पास राजकोषीय गुंजाइश हमेशा सीमित होती है। ऐसे में उसे इसका श्रेय दिया जा सकता है कि ये कदम उठाने के बावजूद वह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की राह से नहीं भटकी। हालांकि चालू वित्त वर्ष में वह राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के दायरे में लाने के लक्ष्य से मामूली रूप से चूक गई, फिर भी वह इसे 3.4 प्रतिशत के स्तर पर रोकने में सफल रही। इसी तरह अगले वित्त वर्ष के लिए 3.4 प्रतिशत का लक्ष्य भी तार्किक ही लगता है। ऐसे में यह कहना मुनासिब होगा कि सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की राह से कदम पीछे नहीं खींचे हैं, अलबत्ता उसकी रफ्तार कुछ सुस्त जरूर हुई है। इस मामले में मोदी सरकार का रिकॉर्ड भी अच्छा ही कहा जाएगा जिसने मनमोहन सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष से विरासत में मिले 4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को काफी हद तक काबू करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने भी इसमें सरकार की मदद की जिनके दाम फिर चढ़ने से मोदी सरकार का गणित बाद में कुछ गड़बड़ा गया। असल में राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर फिसलन सरकार की विश्वसनीयता और साख पर ही सवाल खड़े करती है। इसका असर सरकारी बांड और प्रतिभूतियों पर भी पड़ता है। अगर यह घाटा बढ़ता है तो खर्च के लिए सरकार के हाथ भी बंध जाते हैं। इस पर काबू पाकर ही सरकार के लिए दूसरी मदों में खुले हाथ से खर्च करना संभव हो पाता है।

अवधेश राजपूत

सरकारी खजाने में ऐसे संतुलन से ही किसानों के लिए निश्चित आमदनी योजना संभव हो पाई। मुश्किलों से जूझते किसानों के लिए लंबे अर्से से किसी कारगर योजना की वकालत की जा रही थी। निश्चित आमदनी वाली यह योजना कर्ज माफी जैसी खराब नीति की तुलना में बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसकी सफलता इसी बात से सुनिश्चित होगी कि यह लाभार्थियों तक किस रूप में पहुंचेगी। यदि यह योजना कामयाब हुई तो 12 करोड़ परिवारों यानी देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी तक पहुंचने के दम पर बाजी पलटने वाली साबित हो सकती है। इसी तरह पांच लाख रुपये तक की आमदनी करमुक्त होने से लोगों के पास खर्च योग्य आमदनी बढ़ेगी जिससे उपभोग बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति में सुधार होगा। ऐसे ही ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने से लेकर पेंशन की व्यवस्था करना भी नौकरीपेशा तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा तय करेगा। आयुष्मान भारत भी सरकार की सफल योजना साबित हुई है। इस बार मनरेगा के लिए आवंटन में भी सरकार ने कंजूसी नहीं की। यही स्थिति अन्य वर्गों के सशक्तीकरण में बढ़ाए गए खर्च में भी झलकती है। कुल मिलाकर इससे अच्छा माहौल बनेगा।

वैसे तो बुनियादी ढांचे और उद्योग जगत के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, लेकिन अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही इस सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाए यदि उनमें ही निरंतरता बनाए रखी जाए तो काफी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। सड़क निर्माण से लेकर नए उद्योगों के लिए पूंजी की किल्लत को दूर करने के प्रयास जारी रखे जाएं तो आर्थिक गतिविधियों को गति देने में मदद मिलेगी जो रोजगार सृजन में भी सहायक होंगी। कुछ ऐसा ही सुधारों के बारे में कहा जा सकता है जिसमें कोई नई घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन जो सुधार शुरू किए गए हैं उन्हें ही यदि अपेक्षित रूप से अंजाम तक पहुंचा दिया जाए तो आर्थिक तस्वीर काफी बदल सकती है। जैसे जीएसटी अभी भी संक्रमण वाली अवस्था में है। इसी तरह एनसीएलटी, बिजली एवं बैंकिंग संबंधी सुधारों और दीवालिया संहिता पर भी सही दिशा में बढ़ते रहना होगा। सुधारों के अगले चरण में भूमि और श्रम सुधारों की बारी आएगी जिन्हें चरणबद्ध रूप में आकार देना होगा। बजट द्वारा मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के विजन पर की गई चर्चा को भी व्यापक अर्थों में देखना होगा।

मौजूदा हालत में इस बजट को अच्छा ही कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी काफी कुछ है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे सब्सिडी खर्च को अभी भी तार्किक बनाया जाना शेष है। यह सही है कि सरकार ने अपने खर्च में कई जगहों पर होने वाले रिसाव को रोककर सरकारी खजाने को मजबूती दी है, लेकिन अब इस कवायद को एक नए क्षितिज पर ले जाना होगा। इसकी शुरुआत केरोसिन पर होने वाले खर्च से की जा सकती है। अगर सरकार ऐसा करने में सफल हो जाती है तो फिर उसे अन्य कल्याणकारी मदों में खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। कुल मिलाकर चुनावी साल में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ सौगात देकर भी सरकार ने अपने खजाने के संतुलन को ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया है। यह लोकलुभावन होने के साथ ही तार्किक बजट भी है। इसमें कई कदम ऐसे हैं जिन्हें देश के मौजूदा हालात को देखते हुए किसी भी सरकार के लिए उठाना अपरिहार्य ही था। संयोग से ये कदम उस वक्त उठाए गए जब देश में आम चुनाव दस्तक दे रहे हैं। इसे वक्त के तकाजे के साथ ही चुनावी समीकरणों का संयोग भी कहा जा सकता है।

(लेखक क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

चुनाव की चिंता करने वाला बजट

विवेक कौल

अंतरिम बजट में न केवल पीएम मोदी की पूरी छाप दिखी, बल्कि यह भी दिखा कि यह पूरी तरह आम चुनाव पर केंद्रित है

चंद दिन पहले वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले वित्त मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में लगभग 90 मिनट के अपने भाषण का जब समापन करने जा रहे थे तब सदन भाजपा सांसदों के 'मोदी-मोदी' के नारे से गूंज रहा था। इससे यही साबित हुआ कि यह कार्यवाहक वित्त मंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिम बजट है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की पूरी छाप नजर आई। इसी के साथ यह भी नजर आया कि यह बजट आगामी लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है। कार्यवाहक वित्त मंत्री के भाषण का अधिकांश हिस्सा सरकार के पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों को गिनाने में गया। मुद्रा लोन से लेकर शौचालय और महिलाओं के लिए रसोई गैस कनेक्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से लेकर मुद्रास्फीति की कम दर और स्वच्छ भारत से लेकर बिजली कनेक्शन तक की बातें हुईं। यह सब अपेक्षित भी था। अंतरिम बजट की सबसे उल्लेखनीय घोषणा छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय उपलब्ध कराने वाली रही। अगर इसे राजनीतिक तौर पर देखें तो यह राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी की योजना को सीधे-सीधे सरकार का जवाब है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी योजना का विवरण अभी तक नहीं दिया है। मोदी सरकार की यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम खेती है। इन किसानों को सरकार साल में छह हजार रुपये देगी। यह पैसा साल में तीन किस्तों के जरिये सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा। गौरतलब यह है कि यह योजना एक दिसंबर, 2018 से लागू की जाएगी। सरकार का कहना है कि 31 मार्च, 2019 से पहले दो हजार रुपये की पहली किस्त किसानों को दे दी जाएगी। यानी यह किस्त लोकसभा चुनाव से पहले ही किसानों के खाते में पहुंचेगी। इसके लिए सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

अगर वर्ष 2015-2016 की कृषि जनगणना के आंकड़ों को देखें तो करीब 12.56 करोड़ परिवार सीमांत और छोटी किसानी के दायरे में आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि छह हजार रुपये सालाना के हिसाब से इस योजना पर सरकार का कुल खर्च 75,000 करोड़ रुपये आएगा। प्रश्न यह है कि यह पैसा कहां से आएगा? अर्थशास्त्र में एक कहावत है कि 'देयर इज नो फ्री लंच'। किसी न किसी को तो इसका खर्चा उठाना पड़ेगा। अमूमन ऐसा खर्चा भारतीय मध्य वर्ग ही उठाता है। चूंकि एक तरह से यह विश्व की सबसे बड़ी आय समर्थन योजना होगी इसलिए यह भी देखना होगा कि भारत सरकार के पास इतनी बड़ी योजना चलाने की क्षमता है या नहीं? इस योजना के संदर्भ में एक प्रश्न यह भी उठता है कि इसके लिए कौन योग्य है और कौन नहीं? यह हिसाब लगाना आसान नहीं होगा। भारत के अधिकांश हिस्सों में खेतिहर जमीन के रिकॉर्ड्स कुछ खास विश्वसनीय नहीं हैं। इसके चलते इस पर निगाह रहेगी कि दो महीने से कम समय में सरकारी नौकरशाही इस योजना को किस तरह अंजाम देती है?

इस बजट की एक और बड़ी घोषणा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है। सरकार ने एक पेंशन योजना का एलान किया है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो महीने में 15,000 रुपये या उससे कम कमाते हैं। इस योजना के तहत सरकार ऐसे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये महीना पेंशन देगी। इसके लिए अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्ति को इस योजना का हिस्सा बनकर हर महीने एक निश्चित योगदान देने की जरूरत है। अगर 18 साल का कोई व्यक्ति इस योजना का हिस्सा बनता है तो उसे महीने में 55 रुपये इस योजना में डालने पड़ेंगे। सरकार भी अपनी तरफ से उतनी ही रकम डालेगी। ऊपरी तौर पर यह एक अच्छा इरादा है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि सरकार यह कैसे पता करेगी कि किसी व्यक्ति की कमाई 15,000 रुपये है या उससे कम है? अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे ज्यादातर लोगों को भुगतान नकद में किया जाता है। इसके अलावा उनकी कमाई ऊपर-नीचे भी होती रहती है। ऐसा वेतनभोगी लोगों के साथ नहीं होता। स्पष्ट है कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही इस तरह की योजना को प्रारंभ करना उचित होगा।

2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट की परंपरा को तोड़ा और मध्य वर्ग की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए आयकर पर कुछ छूट दी। अगले वित्त वर्ष से पांच लाख रुपये तक कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस सबके बीच हम अगर सरकार की वित्तीय स्थिति देखें तो पाएंगे कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत रहा। यह पहले के अनुमान 3.3 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा रहा। इसकी प्रमुख वजह यह रही कि साल की शुरुआत में सरकार का यह मानना था कि वह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से करीब 6.04 लाख करोड़ रुपये हासिल कर लेगी, लेकिन फिलहाल 5.04 लाख करोड़ रुपये की ही कमाई अपेक्षित है। जाहिर है कि यह चिंता का विषय है। ऐसे में अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि वस्तु एवं सेवा कर की पूरी प्रणाली को और भी सरल बनाया जाए।

इस पर हैरानी नहीं कि बजट भाषण के अंत में वित्त मंत्री पूरी तरह चुनावी मोड में दिखे और उन्होंने मोदी सरकार के विजन 2030 की भी घोषणा कर डाली। इस विजन के तहत मोदी सरकार ने एक भारतीय को 2022 तक अंतरिक्ष में भेजने की तो बात की है, इसके अलावा देश को प्रदूषण मुक्त करने, पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने, डिजिटल इंडिया पर जोर देने, भौतिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिये रोजगार निर्माण पर भी चर्चा की। दरअसल विजन 2030 के माध्यम से नए सिरे से अच्छे दिन जैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी नरेंद्र मोदी ने इस देश को उम्मीद की किरण की दिखाई थी। उन्होंने रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने और 'न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन' के विचार को लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब यह जगजाहिर है कि ये सब वायदे चुनावी जुमले ही अधिक निकले। इसमें संदेह नहीं अंतरिम बजट के जरिये एक बार फिर 2014 की तरह से उम्मीद जगाने की कोशिश की गई है। देखना यह है कि जनता दोबारा नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास करती है या नहीं?

(लेखक अर्थशास्त्री एवं इजी मनी ट्राइलॉजी के रचनाकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्म-संतुष्टि

एक व्यक्ति नंगे पैर तपती दोपहरी में पैदल जा रहा था। सामने से सूट-बूट पहने दूसरा व्यक्ति गुजरा। उसे देखकर वह सोचने लगा कि इतनी गर्मी में मेरे पास पहनने तक को एक चप्पल नहीं है। इसकी भी क्या किस्मत है? ईश्वर जिसे देता है, छप्पर फाड़कर देता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसने देखा कि एक आदमी व्हील चेयर से जा रहा था, जिसके पास दोनों पैर नहीं थे। विकलांग आदमी को देखकर उसने ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हे प्रभु आपने जितना दिया है, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। फिर सोचने लगा कि खुश रहने और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपके पास जितना है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए।

सुख और दुख सापेक्षिक और आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इच्छाएं मनुष्य का मार्गदर्शन करती हैं और प्रगति के पथ पर अग्रसर करती हैं, परंतु इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पराकाष्ठा विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। ईश्वर मनुष्य को असीम क्षमताओं और प्रतिभाओं से सुसज्जित करता है। ईश्वर सृष्टि का सृजनकर्ता है, उसके द्वारा निर्मित प्रत्येक कृति स्वयं में अनूठी और अभूतपूर्व शक्तियों से युक्त है। वैयक्तिक विविधता के कारण सभी मनुष्य एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। इसलिए किसी एक मनुष्य की तुलना दूसरे मनुष्य से नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की सक्षमता और योग्यता के अनुरूप इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं संजोनी चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वह उक्त विशिष्ट क्षेत्र में महान कार्य कर सकता है। दुर्भाग्यवश मनुष्य संकीर्ण मानवीय प्रवृत्ति के कारण सदैव दूसरों की सफलता, सुख-सुविधा और संपन्नता से स्वयं की तुलना कर दुखी रहता है।

प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में 'संतोषं परम् सुखं' की अवधारणा रही है। सफल और सुखमय जीवन के लिए मनुष्य में आत्मसंतुष्टि का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। इच्छाएं अंतहीन प्रक्रिया और दुख का कारण होती हैं। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा का जन्म होता है।

देवाशीष उपाध्याय

प्रधानमंत्री की पाठशाला

देवेंद्रराज सुथार

छात्रों को यह बात सदैव स्मरण में रहनी चाहिए कि कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षा जिंदगी से किसी भी स्थिति में बड़ी नहीं होती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 'परीक्षा पे चर्चा 2.0' कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को परीक्षा में तनाव से निपटने का मंत्र दिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशभर के छात्रों से बातचीत करते हुए परीक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि कई बेहतरीन सुझावों से भी उन्हें अवगत कराया। इससे हर परीक्षार्थी को अवश्य ही लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने एक प्रेरणादायी गीत की पंक्ति 'कुछ खिलौनों के टूटने से बचपन नहीं मरा करते' के माध्यम से बच्चों से कहा कि एक-आध परीक्षा में असफल या कम अंक आ जाने से जीवन खत्म नहीं हो जाता। विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों से अपनी तुलना या प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद से ही स्पर्धा करनी चाहिए। समय की कीमत का पाठ पढ़ाने के साथ ही प्रधानमंत्री ने अभिभावकों को बाल प्रतिभाओं के नैसर्गिक विकास को लेकर बालमन पर अपनी सोच और अपेक्षाओं का बोझ डालने से मना किया। उन्होंने बच्चों से तकनीक से दूर रहने के बजाय अपने ज्ञान के विस्तार के लिए उसकी मदद लेने की बात कही। निःसंदेह प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई प्रत्येक बात परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने का मूलमंत्र है। प्रत्येक परीक्षा किसी भी परीक्षार्थी से बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की मांग करती है। परीक्षा में उच्च अंकों से उत्तीर्ण होने वाले किसी भी विद्यार्थी के पीछे उसकी की गई कड़ी मेहनत का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

परीक्षा के तनाव से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि छात्रों को साल भर अपना निर्धारित समय चक्र बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि परीक्षा के दौरान पढ़ी हुईं चीजें शीघ्र याद हो जाएं। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को केवल पढ़ते ही रहना नहीं चाहिए, बल्कि लिखने का सतत अभ्यास भी करते रहने चाहिए। लिखने का अभ्यास नहीं होने के कारण कई बार परीक्षाओं में विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर आने के बावजूद भी सटीक उत्तर लेखन को लेकर तारतम्य नहीं बना पाते हैं। विद्यार्थियों को अपनी लिखावट पर भी ध्यान देना बेहद ही जरूर है। कोई भी परीक्षक जब किसी भी परीक्षार्थी की कॉपी की जांच करता है तो सर्वप्रथम उसकी निगाह परीक्षार्थी की लेखनी पर जाती है।

परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को अपना सामान्य व्यवहार रखते हुए सहजता से अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखकर पर्याप्त समय तक ही अध्ययन करना चाहिए। किसी भी चीज की अति उचित नहीं मानी जाती है। इसलिए परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को अपनी नींद से समझौता करके अध्ययन नहीं करना चाहिए। यह बात स्मरण में रहनी चाहिए कि कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षा जिंदगी से किसी भी स्थिति में बड़ी नहीं होती। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो स्कूल की परीक्षा में असफल रहे और जिन्हें किताबी पढ़ाई कभी समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने इसे कमजोरी के रूप में नहीं लेते हुए अपने कौशल और संघर्ष का लोहा मनवाकर कई महान कार्य कर दिखाए। परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे परीक्षा को तनाव की दृष्टि से देखने के बजाय उसे अपनी सफलता के शिखर तक ले जाने वाली एक आनंददायक सीढ़ी के रूप में देखें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना

डॉ. एके वर्मा ने अपने आलेख 'सियासी इंजीनियरिंग की चुनौतियां' में 2019 के आम चुनाव को लेकर जो सियासी तस्वीर पेश की है, उससे लगता है कि अब राजग, संप्रग और राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दलों के आपसी गठजोड़ के बीच त्रिकोणीय चुनावी संघर्ष होने की संभावना बलवती हो रही है। ऐसे में सांप्रदायिक और जातीय धुरी पर टिकी भारतीय राजनीति में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वह यह है कि अब देश की आम जनता का रुझान जातीय और सांप्रदायिक राजनीति से हटकर विकासवादी राजनीति की ओर बढ़ रहा है। मोदी शासन में जन-धन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, शौचालय जैसी जनहितैषी योजनाओं से आम जनता के मन में विकास के प्रति जो व्यामोह पैदा हुआ है, वह न केवल कांग्रेस अपितु जातिवादी राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों की भी नींद उड़ाने वाला है। आम चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं, बावजूद इसके राष्ट्रीय स्तर पर मोदी विरोध में बनने वाले महागठबंधन की कोई तस्वीर उभरती नजर नहीं आ रही है। यह विपक्ष के चुनाव पूर्व बिखराव के संकेत हैं, लेकिन इससे भाजपा को इस मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है कि बिखरा हुआ विपक्ष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो विपक्ष आज बिखरा दिखाई दे रहा है, उसे चुनाव के बाद अपने स्वार्थ में इकट्ठा होते देर नहीं लगेगी। ऐसे में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद भी यदि एक वोट से भी बहुमत से दूर रहती है तो उसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सदन में एक वोट जुटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज पूरा विपक्ष मोदी-विरोध की मानसिकता से ग्रस्त दिखाई दे रहा है।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

प्रेरणादायक फिल्म

रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित फिल्म मणिकर्णिका प्रेरणादायक है। देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना वे निडरता के साथ अंग्रेजों से लड़ीं और उन्हें नाकों चने चबवा दिए। वह नारी शक्ति का प्रतीक बनीं। उनका जीवन यह सीख देता है कि देश प्रेम सर्वोपरि है और देश की उन्नति ही सभी देशवासियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

सौरभ पाठक, ग्रेटर नोएडा

रामदेव का कथन उचित

तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर योग गुरु बाबा रामदेव का यह कथन वाजिब है कि इसके नियंत्रण के लिए देश में सभी के लिए एक समान सख्त कानून जरूरी है। इसमें अधिक बच्चों वाले माता-पिता और परिवारों को सरकारी सुविधाओं और मताधिकार आदि से वंचित किया जाए। इससे निश्चित ही काफी सुधार होगा। मगर दुख की बात तो यह है कि शायद ही कोई पार्टी इस पर विचार करने के लिए तैयार हो।

वेद मामूरपुर, नरेला

शोध का विषय

भारत की आर्थिक विकास दर आजादी के बाद से आज तक दो अंकों तक नहीं पहुंच सकी, जबकि राजनेताओं की निजी आर्थिक विकास दर कई सौ गुना बढ़ गई। जो नेता संघर्ष के दिनों में पैदल या साइकिल पर बैठकर घूमा करते थे, लेकिन सत्तासीन होते ही अरबपति हो गए। अगर जांच एजेंसियां इनकी आय और पारिवारिक संपत्ति की सघन जांच पड़ताल करें तो यह राजनीतिक प्रतिशोध का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शोध का विषय होगा। ऐसा कौन सा फॉर्मूला इनके हाथ लगा कि इनकी आर्थिक विकास दर कई सौ गुना बढ़ गई? जबकि इनको संसद या विधानसभा भेजने वाला मतदाता बेचारा दो वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता है।

रचना रस्तोगी, मेरठ

जीडीपी नहीं सही मापदंड

जीडीपी में देश में वस्तुओं के उत्पादन की गणना की जाती है, परंतु देशवासियों की आय को नहीं मापा जाता। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसका कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में प्रतिदिन वृद्धि करना है। अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने वाला एक पहलू जनसंख्या भी है। ब्रिटेन की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है और भारत की तकरीबन 136 करोड़। भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण जीडीपी बढ़ जाता है। हमारे जीवन स्तर का सही मापदंड आय है, ना कि जीडीपी।

एकता, डॉ. भीमराव आंबेडकर कॉलेज

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कायालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।